

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के सामाजिक अंकेक्षण के तहत गढ़वा में जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन।



गढ़वा

पीएम आवास के सामाजिक अंकेक्षण के क्रम में हुई जन-सुनवाई प्राप्त शिकायतों का निराकरण और सुझावों पर होगा अमल

प्रतिनिधि, गढ़वा

गढ़वा नगर परिषद अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के धरातल पर क्रियान्वयन को परखने के लिए गढ़वा में विशेष सामाजिक अंकेक्षण पिछले 15 दिन से चल रहा है। उसी के क्रम में अंतिम चरण के रूप में सार्वजनिक जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित हुआ। जनसुनवाई में ना केवल लाभुकगण, स्थानीय जनप्रतिनिधि, जिला सामाजिक अंकेक्षण टीम के सदस्य शामिल हुए, बल्कि नगर विकास विभाग रांची के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। सामाजिक अंकेक्षण टीम ने बीते 15 दिन गढ़वा में पीएम आवास योजना (शहरी) के धरातलीय अध्ययन करने के उपरांत जो निष्कर्ष पाया, उसकी रिपोर्ट को जनसुनवाई कार्यक्रम में सार्वजनिक रूप से रखा गया। जन सुनवाई के दौरान कुछ



जनसुनवाई में कार्यपालक पदाधिकारी व अन्य

कमियां भी सार्वजनिक हुईं, जिनको लेकर ज्यूरी के सदस्यों ने कार्यपालक पदाधिकारी से निस्तारण के लिए कहा। कार्यपालक पदाधिकारी संजय कुमार ने कहा कि हमारा राज्य पहला राज्य है जहां प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) का सामाजिक अंकेक्षण आरंभ हुआ था।

कहा कि सामाजिक अंकेक्षण विधि मॉनिटरिंग की एक लोकातांत्रिक प्रक्रिया है। उक्त जन सुनवाई कार्यक्रम नगर परिषद सभागार में संपन्न हुआ। सामाजिक अंकेक्षण इकाई ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत कुल चयनित 10 वार्डों में भौतिक निरीक्षण,

लाभार्थी सभा, संचिकाओं आदि की जांच कर जन सुनवाई की गयी। इस अवसर पर वार्ड पार्षद गण, ज्यूरी के सदस्य, नगर प्रबंधक, सीएलटीसी, पीएमसी कर्मी व सामाजिक अंकेक्षण से राज्य प्रतिनिधि तथा क्षेत्रीय पर्यवेक्षक उपस्थित थे।

नगरीय प्रशासन निदेशालय, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड सरकार